Region. The teachers specially recruited only for North-Eastern Region in 1984 were not considered eligible for Special Duty Allowance. These teachers have however, been given the option/benefit for transfer outside the North-Eastern Region.

Release of funds from National Fishermen's Welfare Fund

2668. SHRI MOHAN BABU: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the amount of funds released in 1994-95 from the National Fishermen's Welfare Fund to Andhra Pradesh;

(b) the total amount of funds released from the National Fishermen Welfare Fund all over the country in 1994-95;

(c) whether Government are making a determined effort to provide housing to fishermen from Andhra Pradesh; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) A sum of Rs. 150 lakhs as Central Assistance was released during 1994-95 under the National Welfare of Fishermen Scheme to the State of Andhra Pradesh.

(b) A total sum of Rs. 1255.65 lakhs as Central Assistance was released during 1994-95 under the National Welfare of Fishermen Scheme to various States/Union Territories participating in the scheme.

(c) and (d) Yes, Sir. Out of a total sum of Rs. 1426 lakhs as Central Assistance released so far under the Development of Model Fishermen Villages Component of the National Welfare of Fishermen Scheme to various participating States/Union Territories, a sum of Rs. 255.03 lakhs representing about 18% share of the total Central Assistance, has been released to the State of Andhra Pradesh for construction of 7040 houses, 50 tubewells and 8 community halls.

भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ित शिक्षकों का स्थानांतरण किए जाने के संबंध में निर्णय

2669. **श्री राघव जी:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री 1 दिसंबर, 1995 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 571 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैस त्रासदी से प्रभावित होने का दावा करने वाले दो शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर न्यायालय के निर्देशानुसार 20 नवम्बर, 1995 तक कोई निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) जी, नहीं।

(ख) यह मामला केन्द्रीय विद्यालय संगठन के विचाराधीन है।

Expiry of exemption granted for Nalidixic Acid

2670. SHRI H. HANUMANTHAPPA:
SHRI RAJNI RANJAN SAHU:
SHRI GOVIND RAM MIRI:

Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that validity of exemption granted for Nalidixic Acid expired on 31st October, 1992;

(b) whether it is a fact that till date the price of formulations have not been fixed and the company has been allowed to mint crores of rupees; and

(c) the person responsible for such a state of affairs and steps being taken to establish the accountability?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI RAM LAKHAN SINGH YADAV): (a) Yes, Sir.

(b) The prices of some formulations based on bulk drug Nalidixic Acid were revised on 6.4.95

(c) Does not arise.

अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा में लगे संगठन

2671. **श्री मूलचंद मीणा:** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय अल्पसंख्यकों और समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के कार्य में लगे आयोगों / निकायों / समितियों के नाम क्या हैं;

(ख) सरकार द्वारा गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक निकाय पर कितना व्यय किया गया था; और

(ग) उन्होंने कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) से (ग)

क्र०	सं०आयोगों/निकायों/समितियों के नाम	किया गया व्यय (रु० लाख में)		प्रस्तुत की गई रिपोर्टों की संख्या और सरकार द्वारा की गई कार्रवाई
		93-94	94-95	
1	2	3	4	5
1.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग	201.00	276.00	इस आयोग ने 12.3.92 से 21.3.93 तक की अपनी पहली रिपोर्ट राष्ट्रपति को 25.8.94 को प्रस्तुत की है। सिफारिशों को की गई कार्रवाई रिपोर्टें प्रस्तुत करने के लिए भेजा गया है जिसके प्राप्त होने पर इसे सभा पटल पर रखा जाएगा।
2.	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग	—	55.00	इस आयोग ने वर्ष 1994-95 की अपनी पहली रिपोर्ट कल्याण मंत्री को 16.11.95 को प्रस्तुत की है और इस रिपोर्ट की सिफारिशों को की गई कार्रवाई रिपोर्ट के लिए संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजा जा रहा है।
3.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	91.00	97.00	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक निकाय है और इसने अभी तक कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। तथापि, इसने पूर्व अल्पसंख्यक आयोग की 14 वार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं जिसमें से 10 रिपोर्टें की गई कार्रवाई के ज्ञापन सहित संसद के दोनों सदनों के सभा पटलों पर पहले ही रख दी गई हैं।